many limitations such as the following:—

(i) Limitations of data

(ii) Limitations of statistical tools used in estimating equations.

(iii) Difficulties involving in development realistic models based on assumptions that conform to Indian conditions.

The author has further pointed out the difficulties of identification of investment, of clasifying various firms into various markets when the firms are mul.iproduct/multi-national firms producing unrelated products; the doubtful reliability of data and the problem of changes in sample size in Reserve Bank of India data which he has relied on; that in fact in certain special cases, increase in the "value" of assets might not imply investment during that period but only "revalued" under special clauses of the relevant legislation. Finally, in calculating the market rates, the author has depended exclusively on the Reserve Bank data which though it covers 80 per cent of the firms, itself undergoes changes (in the sample population of firms) every five years due to the addition of new firms. The justification of the models adopted by him has been mainly intuitive. He has admitted that this has been the main limitation on all studies dealing with investment and that the present study is not an exception.

In the circumstances, Government do not wish to comment any further on a piece of purely academic research as no useful conclusions for policy making can be drawn therefrom.

As regards automatic growth, this has permitted to, among others, all Appendix I indusries.

क, ख और ग वर्ग के राज्यों के लिए सरकारी प्रयोजनों हेतु हिन्दी का प्रयोग

5870. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में क, ख और ग वर्ग के राज्यों के लिए सरकारी प्रयोजनों हेतु किए गए हिन्दी के प्रयोग की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष अलग-अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं और विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । वर्ष 1980 के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लिए मुख्य लक्ष्य यह थे :—

1. जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उनमें देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य रखा जाए । यह भी प्रस्ताव किया गया कि क क्षेत्र में स्थित कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत ख क्षेत्र में स्थित कार्यालय 25 प्रतिशत और ग क्षेत्र में स्थित 10 प्रतिशत देवनागरी टाइपराइटर खरीदें ।

2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सामान्य आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं ।

3. सभी क्षेत्रों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं ।

4. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच 66 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 30 प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 10 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाए ।

5. सभी क्षेत्रों में स्थित सरकारी कम्पनियों तथा निगमों को यह सुझाव दिया गया कि वे हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी के प्रशिक्षण, देवनागरी टाइपराइटर तथा जरूरत के मुताबिक हिन्दी पदों की व्यवस्था करें ।

क, ख और ग क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के छोटे बड़े हजारों कार्यालय स्थित हैं और प्रत्येक कार्यालय से प्रतिशत आंकड़े एकत्र करना न तो व्यवहारिक है और न ही इस प्रकार की विस्तृत जानकारी एकत्र करने पर लगने वाला समय और प्रयास उद्दिष्ट प्रतिफल के अनुरूप होगा । तथापि, वार्षिक कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक समीक्षा विभिन्न स्तरों पर गठित हिन्दी सलाहकार समितियों एवं राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा की जाती है और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए इन समितियों द्वारा उचित प्रबन्ध किए जाते हैं और आवश्यकतानुसार निदेश दिए जाते हैं । इस प्रकार की लगातार एवं बहुस्तरीय समीक्षा के फलस्वरूप सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है ।

News Item captioned "Two Ministers in Assam Are Foreigners".

5871. PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item appearing in *Sunday Standard* dated 18th January, 1981 captioned "Two Ministers in Assam are foreigners"; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) The entire matter is under examination of the State Government for appropriate action. However, there is no M.L.A. by the name Anirul Islam as stated in the news item.

राजस्थान में घटिया सीमेंट

5872. **श्री बुद्धि चन्द जैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट के कितने कारखाने हैं और 1979-80 और 1980-81 में उनमें कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उनके विभाग ने इन कारखानों में निर्मित सीमेंट के स्तर का किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करवाया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या विभाग का संबंधित कन्ट्रोलर, बाड़मेर जिले को गत दो वर्षों से लगातार केवल जे० के० ब्रांड सीमेंट आवंटित करता रहा है जो उक्त जिले के प्रति उसकी घोर उपेक्षा दर्शाता है ; और

(घ) क्या बाड़मेर जिले को गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट का आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चनाना) (क) वर्तमान में राजस्थान में 6 कारखाने हैं जिनमें से मोरक में एक कारखाने में 11 मार्च, 1981 से वाणिज्यिक उत्पादन होना आरम्भ हो गया है । 1979-80 और 1980-81 (जनवरी, 81 तक) के